

भले ही रेपो दर ने बाजारों को चौंका दिया हो, लेकिन यह कदम समझदारी भरा था। आगे और भी बढ़ोतरी की संभावना है।

आरबीआई ने बैल को सींग से पकड़ने का फैसला किया है। इसने मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए रेपो दर में 40 आधार अंकों और नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 50 आधार अंकों की वृद्धि की है। हमारा मानना है कि तरलता की दर और मात्रा दोनों को समायोजित करने की ये एक साथ नीतिगत घोषणाएँ एक सोची-समझी चाल है। दिलचस्प बात यह है कि अनुसंधान स्पष्ट रूप से दिखाता है कि केन्द्रीय बैंक की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा को तभी पहचाना जा सकता है जब केंद्रीय बैंक तरलता संचालन के लिए बाजार की प्रतिक्रिया मजबूत हो। उस हद तक, ऐसा लगता है कि आरबीआई ने एक पत्थर से दो निशाने लगाए हैं और केंद्रीय बैंक को लक्षित मुद्रास्फीति के रूप में मजबूत किया है। वास्तव में, आरबीआई गवर्नर द्वारा की गई मध्यावधि की आश्चर्यजनक घोषणा पिछली प्रथाओं से अलग है। यह उस असाधारण समय का भी संकेत देता है, जिसमें हम रह रहे हैं।

आज दरों में वृद्धि का सबसे दिलचस्प पहलू समायोजन नीति के रुख को जारी रखना है। हालांकि बाजार स्तब्ध नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि आज की दरों में बढ़ोतरी को मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव की बजाय रणनीति के नजरिए से देखा जाना चाहिए। हमारा मानना है कि यह एक व्यावहारिक निर्णय है। अधिक सटीक होने के लिए, वित्तीय प्रणाली में चलनिधि अंतर्वाह या तो केंद्रीय बैंक द्वारा प्रेरित नीति हो सकती है (उदाहरण के लिए भंडार में परिवर्तन, खुले बाजार संचालन आदि) या गैर-नीति प्रेरित (विदेशी मुद्रा भंडार, सरकारी नकद शेष और प्रचलन में मुद्रा)। यह देखते हुए कि गैर-नीति प्रेरित तरलता प्रवाह हाल ही में प्रभावित हुआ है (पोर्टफोलियो पूँजी का बहिर्वाह) और सरकारी उधार कार्यक्रम के विशाल आकार को देखते हुए, आरबीआई को भी कुछ तरीकों से बाजार का समर्थन करने की आवश्यकता है।

सीआरआर (87,000 करोड़ रुपये) के माध्यम से बैंक के भंडार को ज्वल करने से केंद्रीय बैंक को बैंकों से बॉन्ड की खुले बाजार में खरीददारी करने के लिए कुछ जगह मिल सकती है और इस तरह जरूरत पड़ने पर भविष्य में कुछ समय के लिए सहवर्ती तरलता को इंजेक्ट किया जा सकता है। आरबीआई ने 2003-08 के दौरान इसी तरह की रणनीति का पालन किया था जब बाजार स्थिरीकरण बॉन्ड पेश किए गए थे और सीआरआर भी बढ़ा दिया गया था। इस प्रकार सीआरआर दर वृद्धि संभवतः भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल के प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

दुनिया भर में, प्रमुख केन्द्रीय बैंकों ने हाल ही में दर में वृद्धि की है, जो कि अस्थायी प्रकृति के मुद्रास्फीति दबावों की प्राप्ति से संबंधित है। यूएस फेड कीमतों में 40 साल के उच्च उछाल से जूझ रहा है। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आवश्यक दरों में वृद्धि की गति को अनिश्चित शब्दों में सुझाव देते हुए इसने अपने बॉन्ड खरीद कार्यक्रम को काफी कम कर दिया है। यूरोपीय संघ प्रतिक्रिया देने में धीमा रहा है लेकिन जल्द से जल्द इसे ठीक करने के लिए आवाजें उठ रही हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील या रशियन सेंट्रल बैंक जैसे बैंकों ने (बेचमार्क या प्रमुख दरों को दोहरे अंकों में रखते हुए) लगभग पूरी तरह से छलांग लगा दी है।

उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर दोहरी मार पड़ी है- अच्छी तरलता के दिन लद गए हैं। इस हद तक, आरबीआई द्वारा फेड के फैसले से पहले दरों में बढ़ोतरी को आगे बढ़ाने का निर्णय फिर से पूँजी के बहिर्वाह को रोकने का एक प्रयास है।

वर्तमान बाजार की वास्तविकताओं के साथ संरेखित करने के लिए बेंचमार्क दर को आगे बढ़ाने के आरबीआई के फैसले सहित, 21 देशों ने अब तक ब्याज दरों में वृद्धि की है। इनमें से 14 देशों ने 50 आधार अंक (Basis Point (BPS)) से अधिक या उसके बराबर दरों में बढ़ोतरी की है। बाजार आज समाप्त होने वाली अपनी नीति बैठक में यूएस फेड द्वारा 50-बीपीएस की वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, जो 2000 के बाद से सबसे बड़ी है। यह 16 वर्षों में पहली बार होगा जब यूएस फेड लगातार दो बैठकों में उधार लागत में वृद्धि करेगा।

इसके अतिरिक्त, 2021-22 की दूसरी छमाही के दौरान कृषि और गैर-कृषि मजदूरों दोनों के लिए मामूली ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि हुई। हालांकि, इस तरह की वेतन वृद्धि नरम बनी हुई है। सीपीआई बिल्ड-अप में वेतन वृद्धि का भारत योगदान मामूली बना हुआ है और जहाँ तक मुद्रास्फीति की उम्मीदों के निर्धारण का संबंध है, यह एक अच्छा संकेत है।

इस समय आपूर्ति-पक्ष के लागत दबाव को कम करने के उपाय महत्वपूर्ण होंगे, विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल पर करों में एक आंशिक कमी के संदर्भ में। हालांकि, नीतिगत पक्ष पर, इसका मतलब यह होगा कि दरों में बढ़ोतरी के बाद भी, मुद्रास्फीति कुछ समय के लिए उच्च बनी रह सकती है।

चूंकि खुदरा ऋणों को त्रैमासिक रीसेट क्लॉज (ऋणदाता को ब्याज दर की समीक्षा करने और निश्चित वर्षों के बाद इसे रीसेट करने की अनुमति देता है, ताकि यह प्रचलित ब्याज दर के अनुरूप हो) के साथ बाहरी दर (ज्यादातर आरबीआई की रेपो दर के लिए) में बेंचमार्क किया गया है, रेपो दर के लिए बेंचमार्क किए गए ऋण 35-40 बीपीएस की सीमा में बढ़ सकते हैं। दिसंबर 2021 तक, लगभग 39.2 प्रतिशत ऋण बाहरी बेंचमार्क के लिए बेंचमार्क हैं, इसलिए रेपो दर में वृद्धि से उपभोक्ताओं पर ब्याज लागत बढ़ेगी और अगली तिमाही से उन पर प्रभाव पड़ सकता है।

एमसीएलआर (मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट) लिंकड लोन की कुल लोन में लगभग 53 फीसदी की हिस्सेदारी है। सीआरआर में वृद्धि और भविष्य में बेंचमार्क दरों में संभावित बढ़ोतरी के साथ, नेगेटिव कैरी (ऐसी स्थिति जिसमें किसी निवेश या सुरक्षा को धारण करने की लागत उसे धारण करते समय अर्जित आय से अधिक हो) के कारण एमसीएलआर में वृद्धि होगी। इसके अलावा, अगर बैंक जमा दरें बढ़ाते हैं तो फंड की लागत भी बढ़ेगी और बाद में एमसीएलआर भी बढ़ेगा।

आरबीआई ने, हमारे विचार में, बाजार की ताकतों, जो भारत की विकास संभावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं, के जवाब में समझदारी से काम लिया है। साथ ही, प्रोत्साहन के लिए उदार बने रहने और विकास को फिर से जीवंत करने का आश्वासन देकर, इसने देश के विकास में एक विश्वसनीय भागीदार होने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। हमारा यह भी मानना है कि दरों में वृद्धि बैंकिंग क्षेत्र के लिए फायदेमंद होगी क्योंकि जोखिम का उचित मूल्य निर्धारण होगा। हालांकि, अब हमें दरों में बढ़ोतरी की एक श्रृंखला के लिए तैयार रहना होगा।

## जीएस वर्ल्ड टीम इनपुट

**\*IN THE NEWS\***

### रेपो रेट

#### चर्चा में क्यों?

- हाल ही में रिज़र्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अचानक रेपो रेट में बढ़ोतरी की घोषणा की।
- रिज़र्व बैंक ने अब रेपो रेट को 4 फीसदी से बढ़ाकर 4.40 फीसदी कर दिया है।
- हालाँकि, रिवर्स रेपो रेट 3.35 फीसदी पर ही है, लेकिन, सीआरआर में 50 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की गई है।

#### क्या है रेपो रेट?

- आसान शब्दों में अगर बात हो तो रेपो रेट का मतलब है रिज़र्व बैंक द्वारा अन्य बैंकों को दिए जाने वाले कर्ज की दर। बैंक इस चार्ज से अपने ग्राहकों को लोन प्रदान करता है।
- रेपो रेट कम होने का अर्थ है कि ग्राहक अब कम दामों में भी होम लोन और व्हीकल लोन जैसे लोन के कर्ज के दर सस्ते हो जाएँगे।

#### रिवर्स रेपो रेट

- यह रेपो रेट से उलट होता है। बैंकों के पास जब दिन-भर के कामकाज के बाद बड़ी रकम बची रह जाती है, तो उस रकम को रिज़र्व बैंक में रख देते हैं। इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। रिज़र्व बैंक इस रकम पर जिस दर से ब्याज देता है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं।

#### नकद आरक्षित अनुपात

- बैंकिंग नियमों के तहत हर बैंक को अपने कुल कैश रिज़र्व का एक निश्चित हिस्सा रिज़र्व बैंक के पास रखना ही होता है, जिसे कैश रिज़र्व रेश्यो अथवा नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) कहा जाता है।
- यह नियम इसलिए बनाए गए हैं, ताकि यदि किसी भी वक्त किसी भी बैंक में बहुत बड़ी तादाद में जमाकर्ताओं को रकम निकालने की जरूरत पड़े तो बैंक पैसा चुकाने से मना न कर सके।

#### एसएलआर

- नकदी के लिक्विडिटी को कंट्रोल में रखने के लिए एसएलआर का इस्तेमाल किया जाता है।
- आरबीआई जब ब्याज दरों में बदलाव किए बगैर नकदी की लिक्विडिटी कम करना चाहता है तो वह सीआरआर बढ़ा देता है, इससे बैंकों के पास लोन देने के लिए कम रकम बचती है।

### संभावित प्रश्न ( प्रारंभिक परीक्षा )

- प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
- हाल ही में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4 फीसदी से बढ़ाकर 4.50 फीसदी कर दिया है।
  - नकदी के लिक्विडिटी को कंट्रोल में रखने के लिए एसएलआर का इस्तेमाल किया जाता है।
  - वर्तमान में सीआरआर 4% और एसएलआर 18% है।
- उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
- (क) केवल 2  
(ख) 2 और 3  
(ग) 1 और 3  
(घ) उपर्युक्त सभी

### Expected Question (Prelims Exams)

- Q. Consider the following statements-
- Recently, the Reserve Bank has increased the repo rate from 4 percent to 4.50 percent.
  - SLR is used to keep the liquidity of cash under control.
  - Currently CRR is 4% and SLR is 18%.
- Which of the above statements is/are correct?
- (a) Only 2  
(b) 2 and 3  
(c) 1 and 3  
(d) All of the above

### संभावित प्रश्न ( मुख्य परीक्षा )

- प्र. रेपो दर से आप क्या समझते हैं? आरबीआई (RBI) द्वारा हाल ही में रेपो दर में वृद्धि से भारतीय बाजारों पर पड़ने वाले सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए चर्चा करें कि दरों में वृद्धि का फैसला कितना प्रासंगिक है? (250 शब्द)
- Q. What do you mean by repo rate? While highlighting the positive and negative effects on the Indian markets due to the recent increase in the repo rate by the RBI, discuss how relevant is the decision to hike rates? (250 Words)

Committed To Excellence

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।